Demand for simplifying the process of granting scholarships to children of "Safai Karamcharis"

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान) : महोदय, आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। नए-नए विश्वविद्यालय, आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं तकनीकी संस्थान खोले गए हैं, लेकिन इस महंगी शिक्षा का लाभ केवल समृद्ध एवं साधन संपन्न वर्ग तक ही सीमित है। अनुसूचित जातियों के लोगों को आरक्षण द्वारा दाखिलों एवं नौकरियों से जो थोड़ा बहुत लाभ मिला है, उसे भी अब सरकर दक्षता एवं कुशलता के नाम पर कानून बनाकर इस लाभ को छीनना चाहती है।

इसी प्रकार, सरकार वाह-वाही लूटने के लिए हर वर्ष सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं करती हैं। इस वर्ष भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नं. 19 में उल्लेख है कि प्रति वर्ष 6.5 लाख प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के बच्चों को और विशेषकर सफाई कर्मचारियों के बच्चों को दी जाएंगी। मेरा इस संबंध में कहना है कि एक तो इस जाति के बच्चों में भेदभाव के कारण शिक्षा का बहुत ही अभाव है। दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा तय की गई आय सीमा के कारण उनके बच्चे इन छात्रवृत्तियों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा स्कूल एवं कालेज प्रशासन भी इन्हें छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने में आनाकानी करता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, खेल छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु सभी राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दें, अन्यथा ये प्रावधान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे।

Need to evolve a legal framework to protect the interests of internally displaced persons

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I feel proud that we are a nation that has, time and again, welcomed the refugees from across the border and made them feel at home since partition days. Later came the influx of Tibetan refugees along with. His Holiness Dalai Lama, who have made India their home at Dharmsala, and Bylakoppa in Karnataka.The influx of refugees from Sri Lanka is still engaging our efforts.

Sir, despite our commitment to make India a truly secular State, there have been internal conflicts in pockets of communally sensitive areas. Victims from minority communities have been uprooted from their homes and managed to survive in camps in inhuman conditions. Communal carnage in Gujarat had left an indelible scar on our secular fabric as well as the recent attacks at Kandamahal in Orissa. Still fresh in our memory is the happenings at Lalgarh which rendered many homeless. They still live in make-shift camps devoid of basic amenities like water and sanitation.

For enabling resettlement, rehabilitation and reconstruction of the lives of these internally displaced persons, I urge upon the Centre to come up with a legal frame-work on the lines of the National Policy on Resettlement and Rehabilitation evolved for protection of persons displaced by developmental projects. Such a step will reaffirm our commitment to the UN Charter of Human Rights as a truly democratic and secular nation. Thank you.

DR. PRABHA THAKUR (Rajasthan): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri B.K. Hariprasad.